सरकारी व्यय में मितव्ययिता

9338 श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकारी व्यय मे मितव्ययिता करने के लिए गत अगस्त महीने के बाद से क्या उपाय किए गए है ,

(ख) इन उपायो के परिणामस्वरूप प्रत्येक मंत्रालय को हुई मासिक बचत का उपाय-वार ब्यौरा क्या है , और

(ग) गत नवम्बर महीने के बाद से पेट्रौल के औसत खर्च मे की गई मासिक बचत का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) घाटे की वित्त व्यवस्था का कम करने के दृष्टि मे विभिन्न मंत्रालयो विभागो के बजटो मे मितव्ययिता करने के लिए गत वर्ष अगस्त मे कई उपाय किए थे ताकि अर्थ-व्यवस्था मे मुद्रा स्फीति के दबावो को नियन्त्रित रखा जा सके। पहले से प्रभावी मितव्ययिता के उपायो के अलावा, सरकार के आयोजना-भिन्न व्यय मे मितव्ययिता के जो और उपाय किए गए वे थे

आकस्मिकता व्यय और यात्रा भत्तो मे मितव्ययिता , गैर-कार्यात्मक इमारतो के निर्माण का स्थगन जिनमे काम नहीं हो रहा और उनके निर्माण का काम प्लिन्थ स्तर से ऊपर नही बढा। सरकारी इमारतो की वार्षिक मरम्मतो तथा उनके अनुरक्षण का कार्य स्थगित करना, नए पदो के सृजन तथा ऐसे पदो के भरने पर रोक लगाना जो छ मास से अधिक समय से खाली रहे है , सरकार की विभिन्न शाखाओ मे अधिकारियो के बार-बार किए जाने वाले स्थानान्तरण को रोकना ताकि स्थानान्तरण भत्तो मे बचत की जा सके , दफ्तर की गाडियो द्वारा पैट्रोल की खपत मे और टेलीफोन कालो मे बचत, आतिथ्य व्यय और विदेश यात्रा पर खर्च मे किफायत, सम्मेलनो गोष्ठियो और बैठकों के आयोजन से सबधित खर्चों मे किफायत , अन्तर्राष्ट्रीय बैठको के आयोजन के लिए कम सख्या मे लोगो को निमन्त्रित करना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो का मार्ग-दर्शन करना ताकि चुस्त कार्यानिष्पादन आदि से और अधिक आन्तरिक साधन जुटाकर नकदी के रुप मे उनके घाटे को कम किया जा सके ।

2 इसके अलावा, आयोजना व्यय मे भी मितव्ययिता करना आवश्यक पाया गया । यह इस तरीके से किया गया कि ऐसी महत्व-पूर्ण परियोजनाओ और कार्यक्रमो की प्रगति पर जो अत्यावश्यक है और पूर्ण होने को है, कोई बुरा असर नही पडा और ऐसी परियो-जनाओ और योजनाओ की गति कम हो गयी जो अत्यावश्यक नही हैं और जनके पूर्ण होने मे सापेक्षत अधिक लम्बा समय लगेगा । 1973-74 मे राज्यो की आयोजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता मे 100 करोड रूपए की कमी करने का भी प्रस्ताव किया गया था ।

3 यह आशा की गयी थी कि इन उपायो के परिणामस्वरुप लगभग 400 करोड रूपए की बचत होगी । विभिन्न मंत्रालयो विभागो ने आमतौर पर मितव्ययिता के उन उपायो को कार्यान्वित किया है। अगस्त 1973 मे जब से मितव्ययिता के ये उपाय शुरू किए गए है तब से लगातार बचत के इन उपायो को कार्यक्रम किया जा रहा है । इन बचतो का सबध, 1973-74 के पूरे वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयो विभागो की कुल बजट व्यवस्थाओ से है और उपर्युक्त बडी सख्या किए गए मितव्ययिता के उपायो का परिणाम है। यह बताना सम्भव नही है कि अलग अलग महीने मे कितनी कितनी बचत हुई और मितव्ययिता के अलग-अलग उपाय के परिणामस्वरुप कितनी कितनी बचत हुई । विभिन्न मंत्रालयो विभागो में

1973-74 में की गई बचतों का मूल्यांकन संलग्न विवरण में दिया गया है। ये बचतें सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन, खाद्यान्न में राजसहायता के कारण दैवी विपत्तियां आदि के कारण राज्यों की अतिरिक्त सहायता तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं के लिए कतिपय मंत्रालयों/विभागों की कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण सरकार पर पड़ने वाली अतिरिक्त देनदारियों को न तो हिसाब में लेती है और न ही ऐसा कोई अभिप्राय था।

(ग) नवम्बर, 1973 से पहले की तथा उसके बाद की अवधि के बारे में पैट्रोल पर मासिक औसत व्यय की तुलना करना इस स्तर पर सम्भव नहीं है। क्योंकि उस अवधि के प्रमाणित खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

करोड़ रूपयों में

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	कुल बचतें जिनके बारे में सूचना दी गयी
(1)	(2)	(3)
1.	कृषि	13.84
2.	खाद्य	4.47
3.	सामुदायिक विकास	5.40
4.	सहकारिता	10.12
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	3.87
6.	वाणिज्य	0.34
7.	संचार तथा समुद्रपारीय संचार सेवाएं	0.02
8.	डाक-तार	3.29
9.	शिक्षा	11.76
10.	समाज कल्याण	2.48
11.	आर्थिक कार्य (वित्त)	2.93
12.	बैंकिंग (वित्त)	7.50
13.	व्यय (वित्त)	158.45*
14.	राजस्व और बीमा (वित्त)	3.13
15.	स्वास्थ्य	4.60
16.	परिवार नियोजन	6.25
17.	भारी उद्योग	8.54
18.	गृह	1.40
19.	औद्योगिक विकास	8.76
20.	सूचना और प्रसारण	3.68
21.	सिंचाई और बिजली	23.98
22.	श्रम और रोजगार	0.32
23.	पुनर्वास	2.52
24.	पैट्रोलियम तथा रसायन	15.62
25.	नौवहन और परिवहन	24.41
26.	इस्पात	31.72
27.	खान	9.71
28.	पर्यटन तथा नागर विमानन	4.69
29.	निर्माण और आवास	5.30
30.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2.25
31.	प्रधान मंत्री का सचिवालय	0.02
32.	राष्ट्रपति का सचिवालय	0.02
33.	सर्वोच्च न्यायालय	0.01
34.	योजना आयोग	0.06
	जोड़ :	381.47

* इस रकम में, राज्य की आयोजनाओं के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता में हुई बचतों के 93.98 करोड़ रूपये, रोजगार योजनाओं में हुई बचतों के 34 करोड़ रूपए तथा पांचवी पंचवर्षीय आयोजन की अग्रिम कार्रवाई के संबंध में हुई 30 करोड़ रूपए की बचत शामिल है।